फेडरेशन ऑफ क्लास-1 ऑफीसर्स एसोसियेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन, आल इंडिया एलआईसी एम्पलाईज फेडरेशन

मध्य क्षेत्र के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम

प्रिय साथियों , **दिनांक 1 सितंबर 2023**

हम यहां एलआईसी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा जारी अपील का स्वतंत्र हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों/अधिकारियों से लंबित मांगों के समाधान में अत्यधिक विलंब के खिलाफ 12 सितंबर 2023 को दोपहर के भोजन के अवकाश से पहले दो घंटे की बहिर्गमन हड़ताल का आव्हान किया गया है। हमें खुशी है कि संयुक्त मोर्चा की सभी यूनियनों ने सर्वसम्मति से निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघर्ष करने का निर्णय लिया है। आइए, इस एकता को और भी मजबूत करें और दृढ़ विश्वास के साथ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं तथा मध्य क्षेत्र में इस हड़ताल को कामयाब बनाएं ।

अभिवादन सहित

आपके साथी

एच.के. गड़पाल	**निखिल चतुर्वेदी**	**डी आर महापात्र**	**सुबीर भारतीय**
क्षेत्रीय महासचिव	क्षेत्रीय महासचिव	महासचिव	महासचिव
फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन	*नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया*	*सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन*	*ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉइज फेडरेशन*

मध्य क्षेत्र

संयुक्त अपील

12 सितंबर 2023 को भोजनावकाश पूर्व दो घंटे की बहिर्गमन हड़ताल

मांगे :

1. 30 प्रतिशत की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान पर एलआईसी बोर्ड की सिफारिश की तत्काल अधिसूचना जारी हो।
2. एनपीएस में प्रबंधन के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करना
3. 01 अगस्त 2022 से देय वेतन संशोधन के लिए वेतन वार्ता की तत्काल शुरुआत
4. सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती
5. कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मुद्दों पर प्रबंधन के एकतरफा रवैये के खिलाफ

कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के तत्काल समाधान के लिए एलआईसी प्रबंधन और सरकार को हमारा बार-बार अनुरोध अब तक अनसुना कर दिया गया है। इस बीच, कार्यबल के मुद्दे और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दुखद रूप से, कुछ लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के प्रबंधन के प्रयास अक्सर कठिनाइयों को कम करने के बजाय समस्याओं को और बढ़ा देते हैं।

30 प्रतिशत की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान पर एलआईसी बोर्ड की सिफारिश की अधिसूचना में अत्यधिक देरी हुई है। एलआईसी द्वारा पारिवारिक पेंशन में सुधार के मुद्दे पर सरकार को अपनी सिफारिश भेजे हुए लगभग चार साल हो गए हैं। कई पेंशनभोगियों की मृत्यु हो गई है, जिससे उनके परिवार अधर में रह गए हैं। पिछले चार वर्षों से प्रबंधन का लगातार यही कहना रहा है कि एलआईसी ने मंत्रालय द्वारा मांगे गए सभी स्पष्टीकरण दे दिए हैं। यह देरी विशेष रूप से हैरान करने वाली है क्योंकि पेंशन में समान सुधार पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आरबीआई के कर्मचारियों और अधिकारियों तक बढ़ाया जा चुका है। हाल ही में, यही लाभ आरआरबी को भी दे दिया गया। हम यह समझने में असफल हैं कि एलआईसी को लाभ देने में इतनी देरी क्यों हो रही है।

हाल ही में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि एलआईसी ने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया और भारी प्रगति दर्ज करना जारी रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एलआईसी आज एक विश्व स्तरीय वित्तीय संस्थान है। इसने समर्पित सेवाओं के माध्यम से बीमा कराने वाली जनता की विश्वास और प्रशंसा अर्जित की है। सरकार और प्रबंधन इस बात से अवगत हैं कि इस संस्थान के निर्माण में 1956 से लेकर अब तक कर्मचारियों की कई पीढ़ियों ने अपने पसीने और मेहनत से योगदान दिया है। कर्मचारियों के सभी वर्गों और एजेंसी बल की कड़ी मेहनत ने 31 मार्च 2023 तक 5 करोड़ रुपये के निवेश को शानदार ढंग से बढ़ाकर 582242 करोड़ रुपये कर दिया। दुर्भाग्य से, इस योगदान को मान्यता नहीं दी गई है, और कर्मचारियों और अधिकारियों की जायज मांगें सरकारी फाइलों में धूल खा रही हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को कई अभ्यावेदन के बावजूद, सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई है। बोर्ड द्वारा अनुशंसित सुधारों को मंजूरी देने में देरी एलआईसी जैसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण संस्थान के प्रबंधन की कार्यात्मक स्वायत्तता के बारे में बुनियादी सवाल भी उठाती है।

हम एनपीएस को खत्म करने की अपनी मांग पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत प्रबंधन के योगदान को मौजूदा वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की भी मांग कर रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना(एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू किया है। भले ही एलआईसी के डीसीपीएस लाभार्थियों को अब एनपीएस की संस्थागत ढांचा का हिस्सा बना दिया गया है, हमारे बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद फंड में प्रबंधन का योगदान 10 प्रतिशत की पुरानी दर पर जारी है। इस मुद्दे के समाधान में और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने एनपीएस की अधिसूचना की तारीख (22.12.2003) से पहले विज्ञापित/अधिसूचित पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक बार का विकल्प दिया है। एलआईसी में भी, डीसीपीएस की अधिसूचना की तारीख यानी 01.04.2010 के बाद काफी कर्मचारी संस्थान में शामिल हुए हैं। न्याय और निष्पक्षता के हित में, एलआईसी में इन कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह का इस तिथि से पहले अधिसूचित/विज्ञापित पदों/रिक्तियों के विरुद्ध अवसर विकल्प का और दिया जाना चाहिए।

एलआईसी में सभी यूनियनों ने 01.08.2022 से देय वेतन पुनर्निर्धारण के लिए अगस्त 2022 में अपनी मांगपत्र प्रस्तुत किया है। पूरा एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर बातचीत शुरू नहीं हो पाई है. जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस महीने के आखिरी सप्ताह में दूसरे दौर की चर्चा करने जा रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि एलआईसी इस मुद्दे को जल्दी निपटाने के लिए गंभीरता से बातचीत शुरू न करे। सभी संवर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी है. यह संकट विशेष रूप से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी संवर्गों में गंभीर है। 2020 में अधिसूचित 8,000 तृतीय श्रेणी रिक्तियों में से 2700 से अधिक को विभिन्न कारणों से नहीं भरा जा सका। अगले कुछ वर्षों में सभी संवर्गों में कई निकासियां होने वाली हैं, इसलिए नई भर्ती के महत्व पर विचार किया जाना चाहिए।

एलआईसी के इतिहास में पहली बार, अधिकारियों को प्रतिकूल पदस्थापना के कारण पदोन्नति छोड़ने के विकल्प से वंचित कर दिया गया है और कईयों को धमकी भी दी गई और उन्हें जबरन रिलीव कर दिया गया। कुछ लोग मजबूर हो गए वीआरएस लेने के लिए क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थितियों का सामना नहीं कर सकते थे। क्या अपने अधिकारियों को तीन दशक से अधिक की समर्पित सेवा देने पर एलआईसी प्रबंधन यह इनाम देने का विचार कर रहा है? प्रशासन और विपणन दोनों क्षेत्र के अधिकारियों को शनिवार और रविवार को कार्यालय खोलने के लिए कहा जाता है, और पांच दिवसीय कार्यदिवस उनके लिए एक मजाक बन गया है। एलआईसी प्रबंधन को ऐसी प्रथाओं से बचना चाहिए।

विकास अधिकारियों के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लंबे समय से समाधान की राह तक रहे हैं। पेंशन की मात्रा निर्धारित करने के लिए एडीओ अवधि जोड़ने, विकास अधिकारियों के लिए एफसीए को नि:शुल्क बनाने और इसे ईंधन कूपन के रूप में देने और विकास अधिकारियों के लिए लागत-मुक्त कर-मुक्त विपणन व्यय का प्रावधान करने जैसे मुद्दों पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

हाल ही में, प्रबंधन के कामकाज में एकतरफावाद का दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई पड़ा। बिजनेस मॉडल और उच्च प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संदर्भ में एलआईसी में हो रहे व्यापक बदलावों पर कर्मचारी संघों के साथ कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई है। कार्यबल की मेहनत से अर्जित लाभों को कम करने के लिए कुछ अजीब और अतार्किक तिकड़में अपनाई जा रही हैं। सार्वजनिक छुट्टियों की पूरी तरह से अस्थिर व्याख्या देकर एसीएल की मनमानी वापसी और हाल ही में सीएल में बारह दिनों की कटौती प्रबंधन के दृष्टिकोण में नए पाए गए एकतरफावाद के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दुख की बात है कि नए लाभ पहुंचाते समय कर्मचारियों की सद्भावना का उपयोग करने के बजाय, ऐसे कार्य केवल विपरीत प्रभाव ही उत्पन्न करते हैं। दुर्भाग्य से, बदली हुई परिस्थिति में बिना किसी आंदोलन का सहारा लिए एलआईसी की सुरक्षा और मजबूती के प्रति कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रतिबद्धता को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। प्रबंधन को पता होना चाहिए कि संस्थान की प्रगति मुख्य रूप से कार्यबल के समर्थन और निष्ठा पर निर्भर करती है, न कि हाल ही में प्रदर्शित किए जा रहे दिखावटी नैतिक रवैये पर।

इन परिस्थितियों में उपरोक्त मुद्दों पर कड़ा विरोध दर्ज कराना आवश्यक हो गया है। इसलिए, हम सभी एलआईसी कर्मचारियों और अधिकारियों से 12 सितंबर 2023 (मंगलवार) को दोपहर के भोजन अवकाश से पूर्व दो घंटे की बहिर्गमन हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं। हड़ताल की कार्रवाई की तैयारी में, हम यह भी अनुरोध करते हैं कि गेट मीटिंग और दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन 30 अगस्त 2023, 8 सितंबर 2023 और 11 सितंबर 2023 को आयोजित किए जाएं। जहां कर्मचारियों और अधिकारियों को समस्याएं विस्तार से समझाये जाएं।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित...

आपके साथी

-सही-	-सही-	-सही-	-सही-
(एस. राजकुमार)	**(विवेक सिंह)**	**(श्रीकांत मिश्रा)**	**(राजेश कुमार)**
महासचिव	महासचिव	महासचिव	महासचिव
फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास-1 आफीसर्स एसोसियेशन	नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया	ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन	ऑल इंडिया एलआईसी एम्पलाईज फेडरेशन